

लोकसभाध्यक्ष दुविधापूर्ण विडंबना में फंसे

उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को तो पुस्तक के अंश उद्धृत करने दिए पर राहुल गांधी को पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की पुस्तक के अंश पढ़ने की इजाज़त नहीं दी

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके क्योंकि लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। राहुल गांधी को लद्दाख में चीन के हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद यह हंगामा हुआ।
ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में भी भाषण नहीं देंगे और संभव है कि वह राज्यसभा में जवाब दें, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार आखिरी कोशिश कर रही है कि गतिरोध खत्म हो और विपक्ष से बातचीत शुरू हो सके। इसके लिए भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोले गए सभी आपत्तिजनक शब्द हटाए जा सकते हैं। वह किताबों से उद्धरण दे

- लोकसभाध्यक्ष की इस “विवादपूर्ण” व्यवस्था के कारण, कांग्रेस ने भारी हंगामा किया और प्र.मंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर नहीं देने दिया।
- राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों की आपत्ति, कि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की किताब अभी प्रकाशित हुई नहीं हुई उस अप्रकाशित पुस्तक के अंश कैसे लोकसभा में पढ़े जा सकते हैं, के जवाब में कहा, वे प्रकाशित पुस्तक की प्रति साथ लाए हैं, तथा उसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, जब प्र.मंत्री सदन में आएंगे।
- इस विवादित प्रकरण का अन्य पहलू यह भी है कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दावा किया था कि पूर्व सेनाध्यक्ष की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, पर, राहुल गांधी ने कहा कि वे पुस्तक की प्रतिलिपि सदन में लाए हैं।
- तो क्या कांग्रेस, वरिष्ठ मंत्रीगणों के खिलाफ मिथ्यावचन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएगी।

रहे थे और स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
विपक्ष ने पूछा कि, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ व्यवहार के अलग-अलग मानदंड अपना रखे हैं।
इसी के विरोध में कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंच गए और उनसे

कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को पत्रिका के लेख से उद्धरण देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि निशिकांत दुबे को ऐसा करने दिया गया।
इस मुद्दे पर स्पीकर मुश्किल स्थिति में नजर आ रहे हैं।
एक दिलचस्प घटनाक्रम में राहुल

गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब को एक प्रति लेकर आए। उन्होंने मीडिया को वह किताब दिखाई और कहा कि जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वह उन्हें इसकी एक प्रति देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल और मंत्री बिट्टू के बीच झड़प

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। आज सुबह संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन के दौरान गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता को "गद्दार दोस्त" कहा। इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को "देश का दुश्मन" बताया।
बिट्टू तीन बार सांसद रह चुके हैं और रेलवे राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024

- राहुल गांधी जब कांग्रेस सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे, तो वहां से गुजर रहे मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में थे, को उन्होंने "गद्दार दोस्त" कहा, बदले में बिट्टू ने उन्हें "देश के दुश्मन" करार दिया।

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जॉइन कर ली थी।
यह छोटी बहस उस समय हुई जब संसद के मकर द्वार के पास कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। जब बिट्टू पास से गुजरे तो गांधी ने कहा, " देखो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना “राजनीतिक मंच” बनाया

न्यायालय ममता जी की इस रणनीति का “बेबस” मूकदर्शक बनकर रह गया और ममता जी को निर्बाध रूप से पन्द्रह मिनट तक मुख्य चुनाव आयुक्त को भला-बुरा कहने का पूरा मौका मिला

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जजों के सामने चल रही कानूनी सुनवाई को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के खिलाफ एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया और इसमें बड़ी जीत हासिल की।
ममता बनर्जी ने बेहतरीन तरीके से राजनीतिक चाल चली और कोर्ट की कार्यवाही को बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। बनर्जी ने राज्य में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वह बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन बिल्कुल नहीं होने देंगी।
अब जब मतदाता सूची का संशोधन (रोल रिविजन) लगभग पूरा

- इस दुःखद घटनाक्रम का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाता की रणनीति को तृणमूल कांग्रेस ने एक कला का रूप दे दिया है, निरंतर सुधार-संवार कर।
- 56 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए थे, गत सूची पर गहराई से काम करने से। इसके अलावा गत सूची में बहुत से नाम उन व्यक्तियों के हैं, जो मृत हो चुके हैं तथा नियमित रूप से बांग्लादेश से, सीमा पार से, गैर कानूनी घुसपैठिए आकर चुनावों में मतदान करते रहे हैं।
- एसआईआर (वोटर सूची का शुद्धिकरण) 4 नवंबर 2025 को आरंभ हुआ था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में परिवर्तन की अंतिम तारीख 19 जनवरी थी और फाइनल सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होनी है।

हो चुका था और प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, तब ममता को लगा कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। पिछली मतदाता

सूचियों से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिगत “चिकन नैक” रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू

चिकन नैक एक संकड़ा भू भाग है, जो देश के नॉर्थ ईस्ट भाग को शेष भारत से जोड़ता है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी 'चिकन नैक' की सुरक्षा से जुड़े 'शोध' प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट के तहत 40 किलोमीटर लंबे भूमिगत रेल कॉरिडोर के निर्माण का काम जल्द ही तेजी से शुरू किया जाएगा, यह दावा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने किया है।
बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरे तथा सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर-जिसे 'चिकन नैक' भी कहा जाता है-के माध्यम से ही पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भारत से जमीनी रूप से संभव है। भारत की सबसे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले इस संकरे भू-भाग की चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है और यह चीन की चुम्बी घाटी से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हाल के महौनों में बांग्लादेश के

- 20-22 किलोमीटर चौड़ा, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ही चिकन नैक कहते हैं, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और चीन की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है।
- बांग्लादेश के चीन के करीब जाने व चीन की मदद से चिकन नैक हथियाने के दावों के मद्देनज़र भारतीय रेल्वे ने भूमिगत रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया है, क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में भी अंडरग्राउण्ड ट्रैक बाधित नहीं होगा।

चीन के करीब जाने के बाद 'चिकन नैक' को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों ने भारत के पूर्वोत्तर भाग को अलग-थलग करने के उद्देश्य से चिकन नैक को जाम करने की खुली अपील की है, साथ ही कुछ उग्रवादी संगठनों ने इस कॉरिडोर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की अपनी परिकल्पना का हिस्सा बताया है।
इस खंड में भूमिगत रेल लाइन

बनाकर भारत संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना और सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन श्रीवास्तव ने कहा कि यह रेल खंड पश्चिम बंगाल में टिन माइल हाट से रंगापाानी स्टेशन तक चलेगा।
2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान सैन्य योजनाकारों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोत्सवाना से 8 चीते 28 को मध्यप्रदेश आर्येंगे

भोपाल, 04 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर असम से जंगली भैंसा मध्यप्रदेश लाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की।

- असम से जंगली भैंसे भी मध्यप्रदेश लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर केंद्रीय मंत्री यादव से आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल चुनावों पर देर रात भाजपा की बैठक मंगलवार देर रात केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार देर रात पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक अहम बैठक दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार के आवास पर हुई।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद और पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह-प्रभारी बिप्लव देब भी चर्चा में शामिल हुए।
यह बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसमें संगठनात्मक मजबूती, बुध-स्तरीय योजना और समग्र चुनावी रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का प्रमुख फोकस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा

- बैठक का फोकस मुख्य रूप से एसआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीति का जवाब देने पर रहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक रुख अपना रखा है।
- मीटिंग में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद शामिल हुए तथा पार्टी अध्यक्ष नबीन ने हरेक सांसद के साथ अलग-अलग मुलाकात कर फीडबैक लिया।
- सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय बजट को “यंग इंडिया” बजट के रूप में प्रचारित करें। इसके अलावा राज्य सरकार की विफलताओं पर आक्रामक रुख अपनाने और आंदोलन करने का निर्देश दिया गया, साथ ही कहा गया कि चुनाव होने तक आंदोलन जारी रहने चाहिए।

एसआईआर मुद्दे से निपटने की रणनीति पर था। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया।

करीब तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखें। युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया

और बजट 2026 को यंग इंडिया का बजट के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई गई है।
भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए एक बड़ा और दीर्घकालिक प्लान तैयार किया है। इसी योजना के तहत नितिन नबीन ने सांसदों के साथ एक-एक कर व्यक्तिगत बैठकें कीं और उनसे सीधे फीडबैक लिया।
सांसदों को जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की विफलताओं को आक्रामक तरीके से उजागर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जोन-वार आंदोलन शुरू करने को कहा गया है। रणनीति यह है कि इन आंदोलनों को विधानसभा चुनाव तक लगातार सक्रिय रखा जाए।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनावों तक सांसदों से नियमित फीडबैक लिया जाता रहेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार ने सुनेत्रा से मुलाकात की

बारामती (महाराष्ट्र), 04 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को परिवार के मुखिया के रूप में नरम रुख दिखाया। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि

- इससे पहले उन्होंने अजित पवार के बेटों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी।

कोई भी फैसला लेने से पहले अभी एक-दूसरे का साथ देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने रास्ता बंद (रोड ब्लॉक) वाला बयान दिया था।
शरद पवार ने दिवंगत अजित पवार के बेटों से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद वह बारामती में सुनेत्रा पवार के घर गए तथा अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।
वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी की कट-ऑफ पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2025-26 की परीक्षा के लिए कट-ऑफ परसेन्टाइल कम करने के राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका

- राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ने 13 जनवरी को कट-ऑफ परसेन्टाइल असामान्य रूप से कम कर दिया था।

पर बुधवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस चुनौती पर गौर किया और निर्देश दिया कि मामले को छह फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका में परीक्षा बोर्ड की 13 जनवरी की उस अधिसूचना पर सवाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अपनी नम्रता का गर्व करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है। —मारकस

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना: अतिरंजित और अंतर्विरोधों से भरा विमर्श

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना – यह शीर्षक अपने आप में ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। आखिर इस कथित प्रयास के पीछे कौन है? निश्चय ही कोई लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार तो नहीं। और यह भी विचित्र है कि 'जनमानस' को इतना भोला और मूर्ख क्यों दिखाया जा रहा है? आज़ादी के सात दशक बाद क्या सचमुच यह मान लिया जाए कि जनता को इतनी आसानी से बहकाया या ब्रेनवॉश किया जा सकता है कि वह पुराने राजसी प्रतीकों को स्वीकार कर ले, जबकि लोकतांत्रिक मूल्य समाज के हर वर्ग में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं? क्या जनता को इतना भी श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं समझदार है, बजाय इसके कि उसे बिना विवेक और स्वतंत्र चिंतन वाले बच्चों की तरह पेश किया जाए?

लेखक अपने लेख की शुरुआत संविधान का हवाला देकर करते हैं समानता, समान अधिकार और यह सिद्धांत कि कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। ठीक है, यह बात स्वीकार्य और निर्विवाद है। लेकिन इसके बाद वे चतुराई से प्रजामंडल आंदोलन को सामने ले आते हैं और उसे जनसाधारण द्वारा लड़ा गया एक दीर्घ संघर्ष बताते लगते हैं। यहीं समस्या शुरू होती है। इतिहास की सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि प्रजामंडल आंदोलन कुछ गिने-चुने अभिजात, संपन्न और उच्चवर्णीय वर्गों द्वारा संचालित था, जो स्वयं मौजूदा सत्ता में भागिदार थे एवं अब उस सत्ता पर पूर्णतः काबिज होना चाह रहे थे। यह आंदोलन मुख्यतः कुछ शहरी केंद्रों तक सीमित रहा और इसमें व्यापक जनभागीदारी लगभग नहीं के बराबर थी।

इस तरह प्रजामंडल आंदोलन का उल्लेख करके लेखक राजस्थान की आबादी के एक विशेष वर्ग को निरंकुश और दमनकारी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में यह एक कमजोर तर्क है, जो प्राथमिक ऐतिहासिक जांच भी नहीं झेल सकता।

लेखक पूर्वशाही परिवारों के लिए हिज हाईनेस जैसी उपाधियों के प्रयोग पर आपत्ति जताते हैं और तर्क देते हैं कि ऐसी संबोधन शैली मूलतः अपमानजनक है और बोलने वाले को संबोधित व्यक्ति से हीन दर्शाती है। लेकिन यह दावा एक समस्याग्रस्त मान्यता पर आधारित है—कि इन उपाधियों का प्रयोग थोपा गया है। वास्तव में किसी को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने वाली कोई दमनकारी व्यवस्था मौजूद ही नहीं है; इनका प्रयोग अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक स्वेच्छिक चयन है।

राजसी उपाधियों का निरंतर प्रयोग राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिघटना के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। अनेक लोगों के लिए ये उपाधियाँ वंश, स्मृति और ऐतिहासिक निरंतरता के प्रतीक हैं, जो स्थानीय इतिहास और सामूहिक पहचान में रची-बसी हैं। इन्हें दर्शना भाव से नहीं, बल्कि उस विरासत की पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक अभिजात वर्ग को अस्थायी सत्ता की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है।

एयर इंडिया के लोगों में महाराजा जैसे सांस्कृतिक प्रतीक इस बात को और स्पष्ट करते हैं। यह छवि किसी दासवत् दण्डवत होने का प्रतीक नहीं, बल्कि राजत्व की उस परंपरागत धारणा से जुड़ी है जिसमें संरक्षण, संरक्षणदाता-भाव और शासक तथा प्रजा के बीच पारस्परिक दायित्व पर बल दिया जाता था। लोकप्रिय कल्पना में इसका टिके रहना सामाजिक-राजनीतिक ऊंच-नीच का समर्थन नहीं अपितु सांस्कृतिक स्मृति की निरंतरता को दर्शाता है।

इसलिए पारंपरिक उपाधियों के प्रयोग को झूठी चेतना या आंतरिक दासता का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय यह अतीत से निरंतरता बनाए रखने का स्वेच्छिक प्रयास है, जिसके माध्यम से लोग आधुनिक राजनीतिक सत्ता की नैतिक और सांस्कृतिक उथलापन से असंतोष भी व्यक्त करते हैं।

यह भी समझना आवश्यक है कि सामंत प्रतीक केवल पूर्वशाही परिवारों की उपाधियों तक सीमित नहीं है। वे राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान और वैश्विक प्रस्तुति को आकार देने वाली भौतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत विरासतों के व्यापक दायरे में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के छह पहाड़ी किले, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, केवल स्थापत्य अवशेष नहीं, बल्कि पूर्व-आधुनिक राजनीतिक संगठन, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक संरक्षण के स्थायी प्रतीक हैं।

इसी प्रकार जयपुर शहर, जिसे यूनेस्को ने प्रांरिक आधुनिक शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना है, प्रत्यक्ष रूप से राजकीय पहल और शासकीय स्थापत्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ। इसकी योजनाबद्ध ग्रीड संरचना, नागरिक स्थल और खगोलीय-प्रशासनिक सिद्धांतों का समन्वय इस धारणा को चुनौती देता है कि रियासती राज्य स्वभावतः जड़ और पिछड़े थे।

भाषायी और साहित्यिक परंपराएँ भी सामंतवाद की आलोचना को जटिल बनाती हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ दरबारी और प्रशासनिक संदर्भों में विकसित और मानकीकृत हुईं। डिंगल और पिंगल साहित्य, जिसे आधुनिक इतिहासलेखन में अक्सर उद्धेक्षित किया जाता है, वह राजकीय संरक्षण से समृद्ध हुआ और उच्च भारतीय साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला की प्रसिद्ध परंपराएँ भी अभिजात और राजकीय संरक्षण की देन हैं, जिन्हें आज विश्वभर के संग्रहालयों और अकादमिक जगत में सराहा जाता है।

यहाँ एक वैचारिक विरोधाभास उभरता है। जब राज्य और राष्ट्र स्वयं इन सांस्कृतिक प्रतीकों को धरोहर पर्यटन, राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर के लिए उपयोग करते हैं, तब उन्हीं प्रतीकों को संरक्षित करने वाले सामंत वर्ग को नैतिक रूप से खारिज करना विश्लेषणात्मक रूप से असंगत प्रतीत होता है। यह दृष्टिकोण सामंतवाद का महिमामंडन करने या उसकी असमानताओं को अनदेखा करने का आग्रह नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि सामंत संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन उनकी सीमाओं के साथ किया जाए, न कि आधुनिक मापदंड से उन्हें एकरेखीय रूप से खारिज किया जाए।

लेखक लोकप्रिय संस्कृति में राजसी ठाट-बाट के चित्रण से असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते कि ऐसी प्रस्तुतियाँ आधुनिक पूंजीवादी बाजार की उपज हैं, न कि सामंती स्मृति की। क्या बिकता है, यह बाजार तय करता है, न कि भूतपूर्व राजपरिवार। यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्वभर में ऐतिहासिक और राजसी ड्रामा लोकप्रिय हैं— डाउनटउन एबे से द क्राउन तक और गेम ऑफ़ थ्रोन्स से द टयूयूड्स तक। उनका आकर्षण सत्ता समर्थन है, बल्कि दृश्यात्मक भव्यता और कथा-निर्माण में है। विश्व भर में जापान, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन जैसे प्रागैतिहास देशों में सर्वेधानिक राजतंत्र हैं। जबकि भारत में राजकीय उपाधियाँ केवल सांस्कृतिक हैं, क्योंकि राजाओं ने स्वेच्छा बदलते राजनैतिक परिवेश को देख भारत में राजनैतिक विलय करके अपनी राजनैतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहयोग किया। किन्तु क्या आधुनिक जोधपुर में गजसिंघजी या आधुनिक जयपुर में ब्रिगिडियर भवानी सिंघजी के योगदान को नकारा जा सकता है ? यह चिंता कि दर्शक राजसी सौंदर्यशास्त्र से मोहित हो जाएंगे, दर्शकों को कमतर बुद्धिमान मानने की पितृसत्तात्मक धारणा पर आधारित है, मानो वे इतिहास, कल्पना और राजनीतिक समर्थन में फर्क नहीं कर सकते।

लेख का मूल स्वर एक विशिष्ट वर्ग के प्रति वैचारिक शत्रुता से प्रेरित लगता है। जयपुर लितरेचर फेस्टिवल द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्वशासक कहने जैसी सामान्य सांस्कृतिक औपचारिकता को लेखक ने लगभग निरंकुश संवैधानिक संकट जैसा बना दिया जो वास्तव में पिछड़ा पर विवादित टॉपिंग जितना ही गंभीर मुद्दा था। अंततः यह लेख गंभीर वैचारिक व सांस्कृतिक आलोचना से अधिक वैचारिक अतिरेक का अभ्यास प्रतीत होता है, जहाँ ऐतिहासिक संदर्भों के सामान्य उल्लेख को सभ्यतागत पतन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथित खतरे और वास्तविक घटना के बीच असंगति इतनी स्पष्ट है कि यदि लेख से गंभीरता का आवरण हटा दिया जाए, तो यह ज़ेनोफोबिया से उपजी एक हास्यास्पद अतिशयोक्ति भर है ।

— अतिथि संपादक
एल के सिंह,
(डॉक्टर और सामाजिक टिप्पणीकार)

परीक्षा की शुचिता बनाम कक्षा की गुणवत्ता: डिजिटल निगरानी का असंतुलन और प्रस्तावित समाधान



प्रो.अशोक कुमार

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था आज एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। एक ओर हम डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी आज भी इस बात पर केंद्रित है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में नकल न कर पाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, फ्लाईंग स्वायद्व तैनात किए जाते हैं और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग केवल दंडात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल परीक्षा की निगरानी कर लेने से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी? सच तो यह है कि परीक्षा की शुचिता की चिंता तब की जाती है जब कक्षा की गुणवत्ता दम तोड़ चुकी होती है। यदि छात्र को साल भर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं मिला, तो वह परीक्षा में अनैतिक रास्तों की ओर मुड़ता ही है। यह लेख इस बात की वकालत करता है कि तकनीक का उपयोग केवल परीक्षा

केंद्रों पर नहीं, बल्कि साल भर चलने निगरानी नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक इन्वेंट्री होगी जो बताएगी कि संसाधनों का कितना उपयोग हो रहा है।

2. संसाधनों का इष्टतम उपयोग

वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग 'पुलिसिंग' जैसा है। हम छात्र को पकड़ने के लिए तकनीक पर भारी निवेश करते हैं, लेकिन उसे सिखाने के लिए नहीं। हम परीक्षा हॉल में उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाते हैं, लेकिन उन्हीं कैमरों को कक्षा में लगाने से कतराते हैं जहाँ वास्तव में भविष्य गढ़ा जाता है।

यह उपचार पर ध्यान देने जैसी स्थिति है, जबकि आवश्यकता निवारण की है। यदि साल भर चलने वाली 1000 घंटों की कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हो जाए, तो परीक्षा के उन 3 घंटों में किसी सीसीटीवी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तकनीक का असली लाभ तब है जब वह शिक्षण पद्धति को पारदर्शी और जवाबदेह बनाए।

स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट सिस्टम: एक क्रांतिकारी समाधान

शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए "स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट सिस्टम" एक प्रभावी समाधान हो सकता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:—

1. लाइव लर्निंग डैशबोर्ड

केवल रिकॉर्डिंग के बजाय, कक्षाओं को एक लाइव डैशबोर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन या उच्च शिक्षा निदेशालय वास्तविक समय में यह देख सकेगा कि किस कॉलेज में कौन सी

कक्षा संचालित हो रही है। यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक इन्वेंट्री होगी जो बताएगी कि संसाधनों का कितना उपयोग हो रहा है।

2. संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारी

सरकारें करोड़ों रुपये खर्च करके कॉलेजों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और लैब स्थापित करती हैं। अक्सर देखा गया है कि ये संसाधन धूल फांकते रहते हैं या केवल निरीक्षण के दिन ही बाहर निकलते हैं। डिजिटल ऑडिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी धन का उपयोग वास्तव में छात्रों के हित में हो रहा है।

3. शैक्षणिक जवाबदेही और उपस्थिति

अक्सर दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। डिजिटल निगरानी शिक्षकों को उनकी उपस्थिति और शिक्षण के प्रति जवाबदेह बनाएगी। जब शिक्षकों को पता होगा कि उसकी कक्षा का ऑडिट किया जा सकता है, तो शिक्षण की गुणवत्ता और गंभीरता में स्वतः ही सुधार होगा।

डिग्री वितरण बनाम ज्ञानार्जन

वर्तमान में बिना पढ़ाई के डिग्री बांटने की जो प्रथा चल पड़ी है, उसने भारतीय युवाओं की वैश्विक साख को खतरे में डाल दिया है। जब कक्षाएं नियमित नहीं होतीं, तो छात्र केवल पास होने के लिए रट्टा मारते हैं या नकल का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन योग्यतागम्य रह जाती है। कक्षा की डिजिटल निगरानी इस डिग्री मिल संस्कृति पर प्रभावी लगाम लगाएगी।

कार्यान्वयन के व्यावहारिक चरण इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है:—

क. सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना: प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए। यह सेल रैंडम आधार पर विभिन्न कक्षाओं का लाइव ऑडिट करे। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि शैक्षणिक बाधाओं की पहचान करना होना चाहिए।

ख. फीडबैक लूप और श्रेष्ठता का सम्मान: कैमरों का उपयोग दंडात्मक न होकर एप्रिसिएशन के लिए भी होना चाहिए। बेहतरीन शिक्षण करने वाले शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके अन्य कॉलेजों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे एक नॉलेज बैंक तैयार होगा जिसका लाभ उन छात्रों को भी मिलेगा जिनके पास अच्छे शिक्षकों का अभाव है।

ग. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि फुटेज का उपयोग केवल और केवल शैक्षणिक सुधार के लिए हो। डेटा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानूनी और तकनीकी सुरक्षा कवच होने चाहिए।

सुरक्षा और अनुशासन का अतिरिक्त लाभ

कक्षाओं में डिजिटल निगरानी का एक और बड़ा पहलू सुरक्षा है। यह परिसर में अनुशासन बनाए रखने और रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने में रामबाण सिद्ध हो सकता है। छात्र और छात्राएं परिसर में सुरक्षित महसूस करेंगे,

जिससे शैक्षणिक वातावरण और अधिक सकारात्मक होगा।

चुनौतियाँ और विरोध के स्वर

निश्चित रूप से, इस तरह के प्रस्ताव का विरोध निजता और अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर होगा। लेकिन यहाँ यह तर्क महत्वपूर्ण है कि एक सार्वजनिक शिक्षक का कक्षा में शिक्षण निजी कृत्य नहीं, बल्कि लोक कर्तव्य है। जब हम मेट्रो, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर सुरक्षा के लिए कैमरों को स्वीकार करते हैं, तो राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्थल कक्षा में पारदर्शिता से क्यों डरते हैं?

निष्कर्ष: एक नई दिशा की ओर

"परीक्षा की पवित्रता तब तक अधूरी है, जब तक कक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित न हो।" यदि हम परीक्षा के 3 घंटों को कैमरे की जद में रख सकते हैं, तो साल भर चलने वाली 1000 घंटों की कक्षाओं को क्यों नहीं? डिजिटल निगरानी का असंतुलन नहीं

करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमें तकनीक को केवल चेक पोस्ट की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोग करना होगा। जब हमारी कक्षाएं पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण होंगी, तभी हम सही मायने में एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर पाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

—प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

डिजिटल राजस्थान में बढ़ता अकेलापन



भूपेश दीक्षित

राजस्थान आज डिजिटल क्रांति के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 'पांपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स' रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 तक राजस्थान में 10 से 29 वर्ष आयु वर्ग की आबादी लगभग 3 करोड़ होगी। यह वह पीढ़ी है जिसके हाथों में प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी

भविष्य होगा। लेकिन डिजिटल गंधी के इस उजले पहलू के साथ एक अंधरा चुनौती भी तेजी से उभर रही है। आज के युवा अपना अधिकांश समय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और स्कॉलिंग में बिता रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी नींद, एकाग्रता, पढ़ाई, कार्यक्षमता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डिजिटल कंटेंट कंपनियाँ ऐसे अल्ट्राथिन बना रही हैं जो बच्चों और युवाओं को घंटों स्क्रीन से बांधे रखते हैं। समस्या तकनीक के उपयोग की नहीं बल्कि उसके अतिरिंत्रित और व्यसनी स्वरूप की है। ऑनलाइन शॉपिंग, रील्स, लाइक्स, कमेंट्स और स्टेटस अपडेट जैसी गतिविधियों ने युवाओं को आभासी दुनिया में तो जोड़ दिया है लेकिन वास्तविक समाज से दूर कर दिया है। परिणामस्वरूप अकेलापन, तनाव, अवसाद, भावनात्मक अस्थिरता और आत्महत्या के विचार तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकट अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गया बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती

बन चुका है। राजस्थान राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में 5530 लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई यानी औसतन हर दिन लगभग 15 परिवार इस दर्द से गुजर रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्याएँ नहीं बल्कि टूटते सामाजिक ताने-बाने की चेतावनी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता है। सर्वेक्षण बताता है कि जिन राज्यों और उनके जिलों में जहाँ सामाजिक जुड़ाव मजबूत है जैसे—बिहार और उत्तरप्रदेश, वहाँ आत्महत्या की दर कम है। वहीं जिन राज्यों में लोग परिवार और समुदाय से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं जैसे—केरल और तमिलनाडु, वहाँ आत्महत्या दर अधिक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि डिजिटल कनेक्टिविटी मानवीय रिश्तों का विकल्प नहीं बन सकती।

राजस्थान के कोटा, सीकर और जयपुर जैसे शैक्षणिक केंद्रों में लाखों विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। उनके पास ऑनलाइन संपर्क तो है लेकिन

भावनात्मक सहारे का अभाव है जो अक्सर गहरे मानसिक तनाव को जन्म देता है और जिसके दुष्परिणाम हमें आत्महत्या के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर मिलने वाली क्षणिक सराहना वास्तविक अपनत्व का स्थान नहीं ले सकती। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल काउंसलिंग अथवा हेल्थलाइन रॉपॉप नहीं है। जरूरत है व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की जैसे स्कूलों में मेंटल एंड डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम, मेंटरशिप प्रणाली, बुद्धि सिस्टम, सहपाठी सहयोग समूह, खेल-कला गतिविधियाँ और परिवारों में खुला संवाद।

समस्या के समाधान हेतु आगामी राज्य बजट में तीन ठोस प्रमाण आधारित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार, स्कूल-कॉलेज आधारित काउंसलिंग सेवाओं और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान। दूसरा, मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल वेलनेस मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावक जागरूकता अभियान

और तीसरा, युवा साथी केंद्रों और नेहरू युवा केंद्रों को मजबूत कर सामुदायिक संवाद और परामर्श की सुविधाओं में विस्तार।

राजस्थान के पास टेली-मानस, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोताम और युवा साथ केंद्र जैसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। आवश्यकता बता बस इतनी है कि नीति और बजट दोनों के केंद्र में सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि जीवन बचाने का सबसे बड़ा सहारा दवाइयाँ, मोबाइल, इंटरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि मजबूत रिश्ते, सच्ची बातचीत और संवेदनाशील समाज हैं। सरकार द्वारा जनहित में उठाये जाने वाले इन्ही ठोस कदमों से आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार होगा।

—भूपेश दीक्षित,
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं
संयोजक, द राजस्थान मेंटल
हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन
नेटवर्क, जयपुर (राजस्थान)

खेजड़ी बचाओ आंदोलन – अनशन पर बैठे संत की तबीयत बिगड़ी

- लोगों ने खुद को रेलिंग से बांधा; संत बोले-कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे
- अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा

बैठे हैं। उन्होंने निर्णय होने तक पट्टी न खोलने की बात कही है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस फैसला होने तक अनशन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट और बिशोई धर्मशाला के बाहर पुलिस के करीब डेढ़ हजार जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वहीं, बिशोई धर्मशाला में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है।

तबीयत बिगड़ने पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा को एम्बुलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल ले जाते लोग। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। अन्न-जल त्यागकर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे। बस तारीख बता दो, आमरण अनशन खत्म कर चले जाएंगे।

अनशन के दौरान पर्यावरण प्रेमी महेंद्रकुमार आंखों पर पट्टी बांधकर

चेकअप कर रही है। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। संतों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। एडिशनल एसपी (सिटी) चक्रवर्ती सिंह और एडिशनल एसपी (ग्रामीण) बनवारी लाल दोनों ही अनशन स्थल के आसपास ही तैनात हैं। एसपी कावेंद्र सिंह सागर का कहना है कि स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट और धरना स्थल पर करीब डेढ़ हजार जवानों की तैनाती की गई है।

आंदोलन से जुड़े विक्रम बिशोई ने बताया कि धरना स्थल पर 24 घंटे से अधिक समय से अनशनकारियों ने पानी तक नहीं पीया है। कई अनशनकारियों की उम्र 70 साल से

अधिक है, ऐसे में उनकी तबीयत भी नाजुक हो गई है। संत लाल दास महाराज भी डि-हाइड्रेट होकर बेहोश हो गए थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनका सीटी स्कैन किया जाएगा। हमें विश्वास है कि किसी के साथ कुछ गंभीर नहीं हो। धरना स्थल पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा की भी तबीयत बिगड़ चुकी है। उनका बोपी 300 तक पहुँच गया है। उन्हें भी एम्बुलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अनशनकारियों की संख्या को देखते हुए बिशोई धर्मशाला में ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया- 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ तैयार किया जा रहा है। अब तक 50 से ज्यादा बेड लगा चुके हैं। सीएमएचओ डॉ. पुष्कराज साध का कहना है कि सभी मरीजों को चेक किया जा रहा है। जिनकी जरा भी तबीयत कमजोर लग रही है, उन्हें भर्ती किया जा रहा है।

फलोदी जिले से आए श्यामलाल

का कहना है कि मैंने जिला कलेक्टर के माध्यम से रफ्ताने की पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि मेरे समाज के संत आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि या तो वे संत-महात्माओं का आमरण अनशन खत्म करवाएँ या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न लो। श्रीगंगागंग किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष अमर सिंह बिशोई ने कहा कि गूंगी-बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्हें यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमकर रेलवेज वार्मिंग का संदेश दे रहे हैं। जब दुनिया को पर्यावरण के महत्व की जानकारी भी नहीं थी, तब यहां के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने निरालादन दिए थे।

प्रशासन किसी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड है। अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मेडिकल टीम मौके पर ही स्वास्थ्य जांच कर रही है।



पंडित अनिल शर्मा

राशि में संचार करेंगे।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज शुक्र कुम्भ राशि में रात्रि 1:11 पर प्रवेश करेगा। आज चतुरथी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 9:41 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:36 तक, चर 11:19 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:24 तक, शुभ 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:07

राशिफल

गुरुवार 5 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक, सुकमां योग रात्रि 12:04 तक, बव करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज शुक्र कुम्भ राशि में रात्रि 1:11 पर प्रवेश करेगा। आज चतुरथी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 9:41 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:36 तक, चर 11:19 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:24 तक, शुभ 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:07

 **मेघ**

स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बचना हुआ मन का भय दूर होगा।

 **तुला**

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

 **वृष**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा।

 **वृश्चिक**

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

 **मिथुन**

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

 **धनु**

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुमनास से बनने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

 **कर्क**

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

 **मकर**

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

 **सिंह**

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। घर-परिवार में चल रही अपसी मतभेद दूर होंगे।

 **कुंभ**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बतने कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक/पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

 **कन्या**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आज उचित सफलता मिलेगी। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

 **मीन**

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

103 किलो मूंगफली तेल सीज, एक क्विंटल अवधिपार खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया

कार्यवाही के दौरान 1 क्विंटल के लगभग अवधिपार मिली खाद्य सामग्री जिसमें सॉस, मसाले, चाय पत्ती शामिल हैं नष्ट करवाये गये



15 लीटर अवधिपार कॉल्ड ड्रिंक को भी करवाया नष्ट

भीम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही

सरसों तेल का नमूना लिया गया तथा निरीक्षण के दौरान अवधि पार तेल, चाय पत्ती, नमक, मसाले तथा अन्य खाद्य सामग्री लगभग 70 किलोग्राम को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

उन्होंने बताया कि लिए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर में भिजवाया जायेगा तथा जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेन्द्र डांगी तथा सहायक महेन्द्र सिंह शामिल थे। सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित कार्यवाही की जायेगी।

राजसमंद, (कासं)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के आदेशों पर सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा भीम में बड़ी कार्यवाही कर 103 किलो मूंगफली का तेल को मौके पर सीज किया गया तथा कार्यवाही के दौरान 1 क्विंटल के लगभग अवधिपार मिली खाद्य

सामग्री जिसमें सॉस, मसाले, चाय पत्ती शामिल हैं नष्ट करवाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा ने बताया कि भीम क्षेत्र में कमलेश किराणा एंड जनरल स्टोर से मूंगफली के तेल का एक नमूना लिया गया तथा लगभग 103 किलोग्राम मूंगफली के तेल को मौके पर सीज किया गया। उक्त फर्म पर अवधि पार 30 किलोग्राम के लगभग सॉस तथा मसाले को भी

मौके पर ही नष्ट करवाया गया। टीम ने भीम रोडवेज बस स्टैंड रोड स्थित नाकोडा स्वीट्स एण्ड किराणा स्टोर से मूंग दाल तथा मसूर की दाल का एक नमूना लिया तथा लगभग 15 लीटर अवधिपार कॉल्ड ड्रिंक को नष्ट करवाया। टीम ने भीम हॉस्पिटल रोड स्थित गोपालदास लीलाराम किराणा स्टोर पर वार अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित कार्यवाही की जायेगी।

नींव खुदाई के दौरान मिली इंसानी हड्डियां

टोंक, (कासं)। निवाई के बापू नगर कॉलोनी में एक निर्माणधीन प्लॉट की नींव खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हड्डियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बुधवार को निवाई कस्बे के 80 फीट रोड स्थित बापू नगर कॉलोनी का है, जहां मजदूरों ने नींव की खुदाई के दौरान हड्डियां देखीं, जिसके

■ पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

बाद उन्होंने तत्काल काम रोक दिया और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद में सूचना मिलते ही निवाई थाना पुलिस के एसआई राजेंद्र सिंह जाळे के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने निर्माणधीन प्लॉट को सुरक्षित कर हड्डियों को उप जिला अस्पताल निवाई

भिजवाया। पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हड्डियां काफी पुरानी प्रतीत हो रही हैं, उनकी वास्तविक स्थिति और समय का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, वह पहले चरागाह भूमि थी। बाद में निवाई नगरपालिका द्वारा इसे कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जांच कर रही है।

अवैध अफीम व गांजे के पौधे जब्त

उदयपुर, (कासं)। भीण्डर थाना पुलिस ने खेत में लगे अवैध अफीम व गांजे के पौधों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। भीण्डर थानाधिकारी पूनराम गुर्जर मय टीम ने सूचना के आधार पर भीखारनिया गांव में रामदेव तिराये से महेन्द्रसिंह पुत्र भेरुसिंह के चार टुकड़ी खेत से अवैध मादक पदार्थों गांजा की फसल के 10 बोरो हेरें पौधे कुल 369.500 किलोग्राम एवं हेरें पौधे 597.880 किलोग्राम अफीम की फसल के पौधे जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पाल कोलखंडा निवासी हितेश परमार ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि हरीश परमार और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई देवीलाल के पेट में चाकू घोंप दिया था। हमले में देवीलाल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया था। आरोपियों ने हितेश परमार पर भी चाकू से हमला किया था। घायल देवीलाल

■ मरम्मत, रंगरोगन व जलापूर्ति दुरुस्त, नगर पालिका का भी रहा सहयोग

स्वरूप पूरी तरह बदल गया। इसके साथ जलापूर्ति व्यवस्था के लिए भीण्डर क्लब द्वारा नगर पालिका पार्श्व जितेन्द्र साहु को अवगत कराया।

इस पर पालिका के सहयोग से नई पानी की टंकी एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। भीण्डर क्लब द्वारा इन्हें स्थापित कर पूरे परिसर में नियमित और सुचारु जलापूर्ति शुरू की गई। इस अवसर पर भीण्डर क्लब संरक्षक चमन सोनी, पंकज व्याा, अध्यक्ष रत्नेश कोठारी, कोषाध्यक्ष शरद अठावाल, सचिव विकास चव्हाण, पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राठौड़, पवन मंदावत, जितेन्द्र साहु, सदीप सामरिया आदि उपस्थित रहे।

खस्ताहाल महिला स्नानघर का भीण्डर क्लब ने बदला स्वरूप

भीण्डर, (निसं)। महिलाओं की गरिमा और सुविधा से जुड़ा एक सराहनीय उदाहरण भीण्डर नगर में देखने को मिला। एक माह पहले तक जिस सार्वजनिक महिला स्नानघर में जाने से महिलाएं असहज महसूस करती थीं, आज वही स्नानघर अपने बदले हुए स्वरूप के कारण प्रशंसा का केंद्र बन गया है। भीण्डर नगर के एकमात्र सार्वजनिक महिला स्नानघर की बदहाल स्थिति को भीण्डर क्लब ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए उसका स्वरूप बदल दिया है। भीण्डर क्लब की पहल और नगर पालिका के सहयोग से महिला स्नानघर में मरम्मत कायां, व्यापक सफाई, रंगरोगन एवं जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया गया।

महिला स्नानघर में लंबे समय से गंदगी का अंबार और छज्जों पर मधुमक्खियों के छत्ते होने से उड़ती मक्खियों से महिलाओं को परेशानी का



भीण्डर क्लब की पहल के बाद बदला स्वरूप।

सामना करना पड़ता था। नलकूप से आने वाले पानी की अनियमित সরलाई और जर्जर दीवारों के कारण स्नान करना कठिन हो गया था। कई बार शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।

समस्या को गंभीरता से लेते हुए

भीण्डर क्लब संरक्षक कैलाश जांगिड ने पहल करते हुए सबसे पहले पूरे स्नानघर की गहन सफाई करवाई गई और मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाया गया। इसके बाद भवन की मरम्मत कर पूरे परिसर में रंगरोगन कराया गया, जिससे स्नानघर का

कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बनी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पुलिस के लिए अभी रहस्य बनी हुई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उनके बर्तन-चहर, कपड़ों की भी जांच होगी। साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस को साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा।

साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कुछ घंटों बाद ही सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर आया था। जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान मोबाइल में मौजूद टेक्स्ट मैसेज और कथित सुसाइड नोट की भाषा और शब्दों की तुलना पहले पोस्ट किए गए मैसेज से होगी। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुसाइड नोट साध्वी प्रेम बाईसा ने ही लिखा था या किसी ओर से लिख कर पोस्ट किया है।

साध्वी के शरीर के अंदरूनी अंगों

आरती नगर आश्रण से एफएसएल टीमों ने रिववार को एफएसएल सबूत जुटाने शुरू किए थे। इस केस के खुलासे के लिए दो तरीके से पर जांच हो रही है। साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस को साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा।

■ गुत्थी को सुलझाने के लिए उनके बर्तन-चहर, कपड़ों की भी जांच होगी, जिस कमरे में उनकी मौत हुई, वहां की मिट्टी से लेकर कंचा और बालों जैसे 33 अलग- नमूने तक जुटाए गए हैं। साध्वी को जहर दिया गया था या नहीं? इसकी जांच के लिए विसरा का नमूना भी एसएफ एल की लैब में पहुंच गया है

■ पुलिस की साइबर सेल इन मोबाइल का डिलीट रिकॉर्ड रिकवर कर रही है। इसके बाद इन्हें एफएसएल टीम को सौंपा जाएगा

का विसरा जुटाया गया है। विसरा जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में किस प्रकार का पदार्थ (विषाक्त) गया, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि मौत हो गई। अगर विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होती है, तो पुलिस पूरे मामले को जांच आत्मस्थता और हत्या के एंगल से करेगी। तब तक एफएसएल उन 33 नमूनों की भी जांच कर लेगी जो घटनास्थल से जुटाए गए हैं। उस रिपोर्ट

के आधार पर पुलिस पता लगाएगी कि साध्वी को जहर दिया गया या फिर खुद लिया था। अगर विसरा रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में साध्वी के पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश के पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जा सकते हैं।

राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि पहली बार है, जब किसी संदिग्ध मौत की जांच के लिए इतने सैंपल लिए

पुलिस के सर्जिकल स्ट्राइक में मध्यप्रदेश की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड

जयपुर। झालावाड़ पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। डीआरआई जयपुर के इनपुट पर की गई इस संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने 320.72 किलोग्राम संदिग्ध केमिकल और पिकअप व महिंद्रा टीयूवी जन्त कर 5 तस्करी को डिटेन किया है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार 3 फरवरी की रात को झालारापटन थानाधिकारी अल्का और डीएसटी प्रभारी मोहन लाल के नेतृत्व में टीमों ने ग्रेड सेंटर चौराहे पर खड़ी संदिग्ध पिकअप और महिंद्रा टीयूवी को चैक किया।

तलाशी के दौरान पिकअप में घरेलू सामान के नीचे छिपाए गए 6 ड्रम बरामद हुए। इनमें 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन नामक केमिकल भरा था, जिसका उपयोग एमडी जैसी खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है।

प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए तस्करी दीपक (30), जितेंद्र सिंह (41) और शैलेंद्र विलाला (26) निवासी आगर मालवा मध्य प्रदेश ने खुलासा किया कि वे यह केमिकल ट्रांसपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र से कोटा मंगवाया था। वहां से इसे किराये की पिकअप में भरकर मध्य प्रदेश के आगर में जयनारायण उर्फ मामू को डिलीवरी देने जा रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मध्य प्रदेश के सुसनेर में दबिबश देकर मुख्य रिसीवर जयनारायण मामू और उसके साथी रामलाल को भी बंदीच लिया।

मामू से कड़ी पूछताछ के बाद

■ तलाशी के दौरान पिकअप में घरेलू सामान के नीचे छिपाए गए 6 ड्रम बरामद हुए। इनमें 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोफेनोन नामक केमिकल भरा था, जिसका उपयोग एमडी जैसी खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है

पुलिस राजगढ़ जिले के माचलपुर पहुंची। हालांकि मुख्य सरगना रघुनंदन पाटीदार अपनी कार लेकर फरार हो गया, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो वहां पूरी ड्रग्स फैक्ट्री संचालित होती मिली। मौके से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के उपकरण और अन्य केमिकल बरामद किए गए। इस कार्यवाही में मध्य प्रदेश की आगर और राजगढ़ पुलिस का विशेष सहयोग रहा।

इस पूरे ऑपरेशन में डीआरआई जयपुर के इनपुट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी अमित कुमार के अनुसार आरोपियों के खिलाफ एन्डोपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह केमिकल कहां से सप्लाई हो रहा था और इसका नेटवर्क राजस्थान व मध्य प्रदेश के किन-किन हिस्सों में फैला है।

चाकू मारकर छोटे भाई की हत्या

■ बड़ा भाई, भाभी और भतीजी गिरफ्तार एक नाबालिग को किया डिटैन

डूंगरपुर, (निसं)। दोवडा थाना पुलिस ने छोटे भाई की हत्या के आरोप में बड़े भाई, भाभी और भतीजी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना 30 जनवरी को पाल कोलखंडा में हुई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पाल कोलखंडा निवासी हितेश परमार ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि हरीश परमार और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई देवीलाल के पेट में चाकू घोंप दिया था। हमले में देवीलाल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया था। आरोपियों ने हितेश परमार पर भी चाकू से हमला किया था। घायल देवीलाल

को डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोवडा थाने के थानाधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने बड़े भाई हरीश परमार भाभी चंदू देवी परमार और भतीजी अंजना परमार को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी पाल कोलखंडा के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त एक नाबालिग को भी इस मामले में डिटैन किया गया है।

धमका कर अवैध वसूली के मामले में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। जिले की सुखेर थाना पुलिस ने डरा-धमका कर अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी रविन्द्र चारण के अनुसार यह हाईकोर अपराधी दिलीप नाथ गिरोह का सदस्य है। उसके साथ मिलकर पूर्वा में गंभीर घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में डराने-धमकाने, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। सुखेर निवासी अथय डांगी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

जिसमें बताया था कि इंस्टाग्राम के जरिए उससे कर भावी रूपयों की मांग की गई। रूपये नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उल्लेखनीय है कि 5 माह पूर्व आरोपी नारायण दास को महिला वेश में घूमते हुए पकड़ा था। आरोपी पर 10 हजार रूपये का इनाम घोषित था। उस वक्त इसे जमीन मालिक को धमका कर 35 लाख रूपये की अवैध वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर अपराधी दिलीपनाथ के साथ मिल कर इस घटना को अंजाम दिया था।

कार्यालय जिला पटिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर

क्रमांक : साम्जाअधि/2025/3232 दिनांक 28.01.2026

Notice Inviting Bid 02/2025-26

E- Bid for foam based orthopaedic mattresses for various government hostels operating under social justice and empowerment department dholpur are inviting from interested bidder upto 29/01/2026 10:00AM to 08/02/2026 05:00PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in> and <http://sppp.raj.gov.in>) of the state; and social justice and empowerment department website. The approximate value of the procurement is RS. 13.70 Lakhs.

UBN no. SOC2526GLRC00365
UBN no. SOC2526A0335

जिला पटिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, धौलपुर

DIPRC/2008/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड धौलपुर

महकुश पौराहा जी०टी०रोड धौलपुर
फोन नं. 05642-220728, ई-मेल ee.dho.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 3377-84 दिनांक: 23.01.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 98 / 2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड के अधीन विभिन्न कार्यों की उपरोक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रथम में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्न यू.बी.एन. के अनुसार www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rajwater.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी किये जा सकते हैं।

एन.आई.डी.नं.	PHE2526A 5568
यू.बी.एन.	PHE2526WSOB 11450

(जीएनए लवागिा)
DIPRC/1698/2026 अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड धौलपुर

कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी
रानी केदारकावत रोडजल कृषि विविधालय, बीकानेर

निविदा सूचना संख्या 13 (2025-26)

मुख्यालय का नाम कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी, रचामी

निविदा का कार्य केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदाओं की कुल लागत रु. 28.45 लाख

निविदा बेचने की अंतिम तारीख 06.02.2026 को सायं 1:00 बजे तक

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख 07.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तारीख 07.02.2026 को दोपहर 2.30 बजे।

UBN : SKA2526WSOB00137 To SKA2526WSOB00143

आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement act 2012 की शर्तें लागू होंगी।

नोट :- निविदा से सम्बंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट www.raubikaner.org, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp देखा जा सकता है।

रज.हावट.डी/25/19100 भू-संपत्ती अधिकाारी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर

सोहाखान ट्रेनर रोडवेज के पार, अजमेर
दूरभाष नम्बर 0145-2970165, E-Mail Address: seajmer@gmail.com

क्रमांक: अधीक्षण वृत्ताधीक्षण केनलकुवर/2025-26/11853-86 दिनांक : 30/1/2026

निविदा सूचना (NIB No. 12 & 13/2025-26)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों द्वारा निविदा संख्या 12 व 13/2025-26 पंजीकृत एवं अनुमोदी संवेदकों से ऑनलाइन सिस्टम ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाओं की अनुमति लागत राशि रुपये 260.00 लाख है। विस्तृत निविदा सूचना जन सम्पर्क निदेशालय की वेबसाइट पर तथा निविदा प्रथम वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं निविदा से दिनांक 30.01.2026 से दिनांक 09.02.2026 को सायं 06:00 बजे तक डाउनलोड एवं इसी समय तक बिदे प्रस्तुत की जा सकती है। निविदाओं की तकनीकी बिदे दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट एन.पी.पी.पी. पर निविदा संख्या 12 हेतु आई.डी.कमांक PHE2526A5860 और यू.बी.एन PHE2526WSOB12348 तथा निविदा संख्या 13 हेतु आई.डी.कमांक PHE2526A5849 और यू.बी.एन नम्बर PHE2526WSOB12322 से निविदा प्रपत्रों का प्रकाशन किया गया है।

(रामचन्द्र राड़)

अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर वृत्त अजमेर

DIPRC/1766/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा

-- निविदा सूचना संख्या 16/2025-26--
UBN CODE: PHE2526WSOB11492

समुचित वर्ग के सूचीबद्ध सार्वजनिक सेविग के निम्न कार्य करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान कोटो उपग्राम में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं निम्न 2013 के अन्तर्गत पेयजल कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं के उपग्रामों के सम्बन्ध में दिना-निर्देशानुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियमानुसार विहित अलग नमूनास्थ देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, निष्पत्ति प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं दो तिफाका पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑनलाइन वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 02.02.2026 बात: 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदाएं इसी वेबसाइट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 02.02.2026 से दिनांक 12.02.2026 तक सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते हैं। वेबसाइट पर उनके सम्बन्ध दिनांक 13.02.2026 को इस कार्यालय में दोपहर 2:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्य दिवस को उसी समय पर निविदा खोली जायेगी। निविदा शुल्क / प्रतियोगी शुल्क निविदादाता द्वारा ऑन लाईन बालान द्वारा निविदा प्रपत्रों में विवद अनुसार इस कार्यालय में सभी निविदा प्राप्ति की दिनांक 13.02.2026 तक को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं :-

- www.dipronline.org
- <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>
- <http://sppp.rajasthan.gov.in>

DIPRC/1749/2026 "जल ही जीवन है"

(अभिषेक मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम कोटा

निदेशालय खाद्य एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदेश.ख.अ. नीलामी। निलामी (ML01)/2026ई - 14179

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्याम खनिज रिहायत निगमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत निम्नांकित प्लॉटों के आधुन ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बोली आमंत्रित की जाती है। शक्ति विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	खनिज का नाम	कुल प्लॉट
चित्तौड़गढ़	निम्बाहोड़	गढ़वाडा	मैग्नेसी स्टोन (एन-सेण्ड हेतु)	2
डींग	सीकरी	बारबुआ	मैग्नेसी स्टोन	4
सवाई माधोपुर	बजीपुर	श्यारोली	मैग्नेसी स्टोन	9
चित्तौड़गढ़	भदोसर	भालोटे	मार्बल	6
झालावाड़	बकानी	बरखेडा कलां	मैग्नेसी स्टोन	5
बाड़मेर	रामसर	भाधभर	मैग्नेसी स्टोन	10
कोटा	चेवट	चेवट	लाइमस्टोन (ग्रायमेनगल) व मैग्नेसी स्टोन	3
जोधपुर	ओरियावां	बैठावांसां	सैंड स्टोन	20
बूंदी	मैनावा	मीनावां	रेड ऑकर, यैला ऑकर व घाघावा कले	2
बाड़मेर	बाड़मेर	सुरा नरपताना	मैग्नेसी स्टोन	5
जोधपुर	बालेसर	सुडियावा	सैंड स्टोन	5
जोधपुर	बालेसर	दानसिंह नगर	सैंड स्टोन	7
जोधपुर	बालेसर	सुडियावा व दानसिंह नगर	सैंड स्टोन	1
जोधपुर	बावडी	कास्टी	सैंड स्टोन	10
			कुल प्लॉट	89

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.,
जी-1/138, नालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017 फोन: 0141-2751417
E-mail- raj_coop_press@yahoo.co.in in Website : www.thecooperativepress.com

क्रमांक/उपरास/प्रा/388-ख/2025-26/2655 दिनांक 05.02.2026

NIB Code: SML2526A0001 **निविदा सूचना** NIB Ref. No: RSM/Tender/2026-27

सुभाग्यवश प्राप्त 2026-27 (31.03.2027 तक) की अंतिम की रिसे रुब - रुम पर अस्वच्छतासुर प्रथिमा प्रवर्ध की रुबानी कया / कवरी हेतु निम्नलुकर (दृढिधता प्राप्त) विविधरे उन्नीअ की जती है:-

क्र. सं.	विवरण	निविदा प्रत्येक	अनुमानित रु.	कवरी जितनी रु.	बिदे रुब	केसेल रु.	बिदे प्रवर्ध रुबो की अंतिम बिदे
1	निविदा प्रवर्ध के अन्तर्गत का कया	अंतिम रु.	रु. 1000 रुब	रु. 38.00 रुब			

पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ‘‘गाली’’ निकाली

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर आपत्ति जताई तो सभापति ने अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाया

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। पूर्व यूडीएच मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ‘‘गाली’’ निकाल दी। जिस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई, इसके बाद सभापति ने उनके द्वारा बोले गए अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकलवाया।

दरअसल धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कहा था कि ‘‘अगर लाखों युवाओं को स्मिफिट ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य नहीं बनाया तो यह युवा आबादी चुनौती बन जाएगी।’’ उनके इस बयान के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा ‘‘ इस देश में एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया।’’ इस दौरान गर्ग को जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा, आपकी बात आधी समझ आती है...लेकिन आधी नहीं। इसी दौरान धारीवाल ने गर्ग को संबोधित करते हुए गाली निकाल दी।

धारीवाल की बात खत्म करने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक ने खड़े होकर आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा कि आदत के मुताबिक धारीवाल ने आज सदन में फिर्त गाली दी है, उसे सदन की कार्यवाही से हटया जाए। जिस पर सभापति ने गाली को कार्यवाही से हटाने के

- इससे पूर्व धारीवाल ने प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
- उन्होंने सड़कों के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी द्वारा सदन में दिए गए जवाब में भी झूठ बोलने के आरोप लगाए

आदेश दिए। ज्ञात रहे कि शांति धारीवाल पहले भी सदन में गाली दे चुके हैं, उस वक्त भारी हंगामा हुआ था और उन्हें सदन से माफ़ी मांगनी पड़ी थी।

इससे पहले शांति धारीवाल ने जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं सड़कों के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी पर भी सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना को लेकर सीएजी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है।

रिपोर्ट में एक करोड़ 32 लाख में से 95 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। धारीवाल ने

आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से फर्जी स्किल सेंटर खुलवा दिए हैं, इसलिए घोटाला किया गया है। बैंक खातों का कोई विवरण नहीं है, फर्जी फोटो और फर्जी फिंगरप्रिंट और एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान किया गया है। धारीवाल ने कहा कि जिन युवाओं ने आपको सत्ता में बैठाया है, कल वही आपके लिए चुनौती बन सकते हैं।

हमारे कार्यकाल में 70 हजार किमी सड़कें बनीं

शांति धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2024-25 में आई थी, उसमें पेव नंबर 12 पर लिखा है कि कांग्रेस के शासन में 70 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सदन में झूठ बोला है।

धारीवाल ने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में 14,800 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है, जबकि हमारी सरकार के दो साल के शासन में ही 23 हजार 585 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यह भी

पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से झूठे भाषण सदन में नहीं देना चाहिए था।

नाम हटाने से विचारधारा खत्म नहीं होगी

धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक-एक करके हमारी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। हमने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वो गरीबों, छात्रों और मजदूर किसानों के हित की योजनाएं थी। मनरेगा में ग्राम सभा का अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया है।

शांति धारीवाल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अहिंसा के आविष्कार करने वाले महात्मा गांधी का नाम ही योजनाओं से हटाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि ‘‘महात्मा गांधी का नाम दुनिया की जबान, दुनिया के दिल और दुनिया के दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। महात्मा गांधी की मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते हैं।’’

‘‘खेजड़ी बचाओ’’ आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

कांग्रेस विधायक डुंगरराम ने कहा कि ‘‘लाखों लोग महापड़ाव में बैठे हैं, 29 संत और 339 पुरुष आमरण अनशन पर हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की।’’

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शुन्यकाल में पच्ची के जरिए मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति बिस्नोई समाज की अगुवाई में पिछले दो साल से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी की अंधाधुंध काटई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, इसे बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। गेदर ने कहा कि सरकार को पता था इसके बावजूद आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की।

लाखों लोग महापड़ाव में आए। आज तीसरे दिन भी 29 संत अन्न, जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। करीब 339 पुरुष अन्न,जल त्याग कर बीकानेर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तीन धरतार्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है, कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने भी कहा कि ‘‘साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें’’

पर नहीं गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें। खेजड़ी राज्य वृक्ष नहीं देव वृक्ष भी है, लोग पूजते हैं। आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। कांग्रेस विधायक डुंगरराम गेदर ने कहा कि 10 नवंबर 2024 को जब बिस्नोई समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव

डाला था। उस समय खींवसर का उपचुनाव था। सरकार को लगा कि खींवसर का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में बिस्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन दिया गया। चुनाव निकल गया, चुनाव जीत लिया, मुद्दे को जुमले की टोकरी में डाल दिया गया, कानून क्या बनाना था।विधायक डूंगरराम ने कहा कि, एक साल बाद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेड़ काटने पर 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग की लकड़ी काटने पर जो 6 महीने की सजा थी, उसकी जगह मात्र 5000 रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की और आसानी से परमिशन मिल गई। आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं?



जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉ. लीलाधर दोचानिया के नव प्रकाशित कविता संग्रह ‘‘जिन्दगी मुस्कराते रहे’’ का विमोचन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक त्रिलोक चंद कौशिक करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित साहित्य संगीत और चित्रकला के त्रिआयामी उत्सव पिकनैफेस्ट के दौरान महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार मनीषा खटाते सहित विभिन्न स्थानों के अनेक लेखक भाग लेंगे। संयोजन सीमा वालिया करेंगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति भारी उत्साह

जयपुर (कासं)। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। करीब 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी

- 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक लोगों ने किया आवेदन
- योजना में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
- 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का प्रावधान

को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के प्रति युवाओं की बेहतर प्रतिक्रिया रही है। अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है, 22 जनवरी को आवेदन शुरू किए गए थे। जिला महाप्रबंधकों द्वारा इन आवेदनों की जांच

कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए शीघ्र ही बैंकों को अप्रेषित किए जाएंगे।

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही, चूरू, बीकानेर, टोंक, और हनुमानगढ़ जिलों में 200 से अधिक आवेदन आए हैं। बूंदी, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, दौसा,

डीडवाना कुचामन, बारां, झुंझुनूं, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, पाली और अलवर जिले ऐसे हैं, जहां 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।ज्ञात रहे कि इस योजना में 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैनुयैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नाक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैनुयैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

‘आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा पोषाहार दे रहे, जिन्हें कुत्ते भी नहीं खाए’

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक रमिला खड्गिया ने जनजाति मंत्री पर आरोप लगाते हुए तंज कसते। मां बाड़ी केंद्रों पर 4-4 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा।

जो पोषाहार आ रहा है, जो एक रुपए के विरिक्त का पैकेट आ रहा है, उसको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा पोषाहार पहुंच रहा है, जो कुत्ते भी नहीं खाए, आप चेक करो। आप मंत्री हो, चेक क्यों नहीं करते हैं। इस पर टीएंडी मंत्री ने कहा कि आपकी अध्यक्षता में ही कमेटी बना देता हूं। इससे पहले उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी के लोग लगने चाहिए, लेकिन आपने जनरल को लगा दिया। मंत्री ने अपने रिश्तेदारों के कहने पर टीएसपी क्षेत्र में नौकरी लगा दी। गत 3-4 महीने से शिक्षकों को पेंसेंट नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, चेक करके देखो।

‘ धौराला में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन कार्य अग्रिम चरण में है ’

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अलेवर जिले की राजगढ़ तहसील के धौराला राजस्व गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन का काम अग्रिम चरण में है।

कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों के पात्र परिवारों के लिए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) में आने के कारण इसका उपयोग उद्योगों

- उद्योग मंत्री ने कर्नल राठौड़ सदन में बताया कि ‘‘राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।’’

के लिए नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल 114 प्लॉट उपलब्ध हैं, इनमें 110 प्लॉट आवंटित तथा 4 रिक्त हैं। इस क्षेत्र में कुल 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 25 एकड़ उद्योगों तथा शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग स्थापित हैं। खनन प्रतिबंधों के कारण इन उद्योगों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध रिक्त

भूखण्डों को देखते हुए राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्व गांव धौराला में 27.68 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम मुण्डजोडी में 27.37 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिह्नित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय-समय पर लिखा गया है।

आवासहीन परिवारों की संख्या के सवाल पर मंत्री खर्चा और सुभाष गर्ग के बीच नौकझोंक

दरअसल प्रश्नकाल में आर.एल.डी. विधायक सुभाष गर्ग ने आवासहीन परिवारों की संख्या पूछी थी, लेकिन यू.डी.एच. मंत्री खर्चा पीएम आवास योजना को लेकर जवाब देने लगे थे

जयपुर (विसं)। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्चा भी सदन में विपक्ष के सवालों में उलझकर रह गए। प्रश्नकाल के दौरान विवाद की शुरुआत आर.एल.डी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई। गर्ग ने भरतपुर में आवासहीन परिवारों की संख्या और पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों पर सवाल पूछा था। सही जवाब नहीं मिलने पर विधायक सुभाष गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बहस और नौकझोंक होत रही।

मंत्री खर्चा के जवाब से असंतुष्ट सुभाष गर्ग ने कहा कि पहले आवासहीन परिवारों की संख्या बताइए जिस पर मंत्री खर्चा, पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें बताते लगे। उनके जवाब पर गर्ग ने आपत्ति करते हुए कहा कि

- इस बीच अन्य मंत्रियों ने मंत्री के पक्ष में जवाब देने की कोशिश की तो नेता प्रतिपक्ष ने भी आपत्ति जताई

होमलेस पॉलिसी-2022 में आवासहीन परिवारों के सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं। मैंने तो इस पर जवाब मांगा था मैं तो हां-ना में जवाब मांग रहा हूं।

जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्चा ने कहा कि भरतपुर में पीएम आवास योजना के 80 फीसदी पूरे हो चुके हैं। गर्ग ने कहा कि, भूमिहीन परिवारों की संख्या पर सवाल किया है।

जिनके पास भूमि ही नहीं है वो आवासहीन कैसे होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन भूमि होगी। जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो बेघर कहलाएगा। आवासहीन नहीं। जिसके पास रहने का ठौर नहीं, वो बेघर है। जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन जमीन है वो आवासहीन कहलाएगा।

इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक नौकझोंक होती रही। यूडीएच मंत्री ने कहा कि भूमिहीन परिवारों की संख्या चाही है तो कलेक्टर से रिपोर्ट मांगाकर दे देंगे।

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने यूडीएच मंत्री के जवाब के बीच दो मंत्रियों के खड़े होने पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं होती।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि आप साल पूछिए भाषण देने का अधिकार नहीं है। जुली ने कहा सच्चाई बता दी तो कहा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जुली ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री जल्दीबाजी कर गए उन्होंने आवासहीन का सवाल पूछा था, सदस्य ने गलती कर दी कि होमलेस पॉलिसी पर पूछ लिया। इन्होंने आवासहीन समझ लिया बात एक ही है। सवाल इतना सा है कि जिनके पास मकान नहीं है मकान कब तक दोगे? जवाब गलत आया इसलिए कहा कि 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई, तो उसका मापदंड पूछे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद को ज्यादा काबिल साबित करने के चक्कर में मंत्रीजी को और मरवा दिया।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ कंकाणी को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे

जयपुर, 4 फरवरी। जैसे-जैसे देश डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी आवश्यकता के रूप में उभरी है। इसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी। इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोरस घोषित करेगी। इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए फास्ट-ट्रैक लैण्ड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कॉन्डिनेशन और सिंगल विण्डो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत इंडिया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान दिए जाएंगे। यह नीति सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित

भी करेगी। प्रदेश में निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी तथा स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, नोडल विभाग होंगे।

के लिए दो समितियों-स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी (एसएलएफसी) और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

संसद में भारी हंगामा, प्रमंत्री भाषण नहीं दे सके

नई दिल्ली, 04 फरवरी। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होने वाला भाषण भी टल गया है। प्रधानमंत्री मोदी को आज शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इससे पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे, और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक गद्दार जा रहा है। इसका चेहरा देखो।" इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहा, "हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।"

मंत्री ने गांधी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए कहा, "देश के दुश्मन।" यह बातचीत उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने (बिट्टू) प्रदर्शनकारी सांसदों के बारे में कहा था कि "वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो।"

ममता बनर्जी ने सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसका चुनाव पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। बनर्जी और उनकी पार्टी ने बंगाल में फर्जी मतदान करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने मतदाता सूचियों की खामियों का फायदा उठाकर कई सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी को मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी नामों की पूरी जानकारी रहती थी और वह नियमित रूप से अपने समर्थकों को फर्जी मतदान के लिए भेजती थी।

कम से कम 56 लाख नाम ऐसे पहचाने गए हैं जो फर्जी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हटाए गए, जिनके नाम पर दर्ज लोग बहुत पहले मर चुके थे। इसके साथ-साथ बांग्लादेश से सीमा पार कर आए अवैध प्रवासी भी बंगाल के चुनावों में नियमित रूप से मतदान करते रहे थे।

इन सभी समूहों को मिलाकर देखा जाए तो मतदाता सूची का सही और ईमानदार संशोधन बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाने का कारण बन सकता है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ममता बनर्जी को ऐसे

- पर, यह महसूस करते हुए कि अगर, संशोधित वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में "ड्रामा" करने का निर्णय लिया। अगर, सुप्रीम कोर्ट इस "ड्रामे" से प्रभावित होकर, एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित कर देता है तो प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा।

फर्जी वोटों से फायदा मिलता रहा है और अब उन्हें इसमें समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए वह इस प्रक्रिया को बदनाम करने और खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।

दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनौती का सामना नहीं कर पाया और ऐसा लगता है कि वह उनके राजनीतिक दबाव के आगे झुक गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के राजनीतिक दांव का सामना नहीं कर पाता और मतदाता सूची का सही संशोधन खतरे में पड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र और मतदान के लिए दुखद दिन होगा।

अदालत में उनके राजनीतिक भाषण को रोकने के बजाय, जज उनके दबाव वाले तरीके के सामने झुक गए और उन्हें लगभग पंद्रह मिनट तक बोलने दिया। अदालत ने मुख्य चुनाव

आयुक्त को निर्देश दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अपनाई जा रही पद्धतियों, पर ध्यान दें।

अदालत तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर आगे सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में नामों में छोटे-मोटे अंतर के आधार पर लोगों के नाम मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं।

बनर्जी ने नाम और उपनाम लिखने के अलग-अलग तरीकों की ओर ध्यान दिलाया, जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी अंतर के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

भूमिगत “चिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इस पट्टी की संवेदनशीलता को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि इस हिस्से में किसी भी प्रकार का व्यवधान सैन्य आपूर्ति लाइनों को काट सकता है और सैनिकों की आवाजाही में बाधा डाल सकता है, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को भी अलग-थलग कर सकता है। एनएफआर अधिकारियों के अनुसार, भूमिगत रेल ट्रैक आपात स्थितियों में भी निर्बाध सैन्य आवागमन सुनिश्चित करेगा। हाल के महीनों में बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव साफ तौर पर दिखाई दिया है। हाल ही में बांग्लादेश वायुसेना ने चीन के साथ ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है।

शरद पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने एनसीपी(एसपी) के साथ विलय की कोई पहल नहीं की थी। शरद पवार ने कहा कि फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच हुई विलय संबंधी चर्चाओं का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिलचस्प बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने किताब की प्रति दिखा दी है। क्या यह वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है? स्थिति अब काफी कटु और खराब हो गई है और सत्तारूढ़ दल और राहुल गांधी के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस सत्र को सामान्य बनाना मुश्किल लग रहा है।

बोत्सवाना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की सफल बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता नजर आएगा।

प.बंगाल चुनावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) राज्य के दौरो के बाद सांसदों के साथ की जा रही ये वन-टू-वन बैठकें पार्टी की चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। चुनावों से पहले इस बैठक को

भाजपा की डिनर डिप्लोमैसी के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी के भीतर समन्वय को मजबूत करना और पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक नैरेटिव को और तेज़ करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल को उस स्तर तक कम कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने असामान्य रूप से बहुत कम बताया है। इसमें कट-अफ

परसेंटाइल को शून्य और नकारात्मक तक कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए योग्यता मानकों को कम करना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बैच ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के तहत नोटिस सावधानी से भेजे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ईसीआई को, कृपया नोटिस सावधानी से भेजें। आप प्रतिष्ठित लेखकों आदि को नोटिस नहीं भेज सकते।" ये टिप्पणियां उस घटना के कुछ हफ्तों बाद आई हैं, जब चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त), नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कई सार्वजनिक हस्तियों को एसआईआर के तहत नोटिस भेजे थे।

ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महिलाओं के नाम केवल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम बदल लिया। उन्होंने कहा, "मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है, वह पति का सरनेम इस्तेमाल कर रही है, इसे भी मिसमैच माना गया, कुछ बेटियां ससुराल चली गईं, उनके नाम भी हटा दिए गए।"

युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मु.मंत्री पद की शपथ ली

इंफाल, 04 फरवरी। हिंसाग्रस्त मणिपुर को लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मार्शल आर्ट के धुरंधर मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। इससे पहले आज उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

वहीं, भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने मणिपुर के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। किपगेन कुकी समुदाय से हैं। इसके अलावा, नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भाजपा के गोविंददास कोथीजम और एनपीपी के के लोकेन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से डिजिटल माध्यम से शपथ ली। विधायक दल की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें खेमचंद (62 वर्षीय) को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल

- कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया

की डेढ़ घंटे बैठक चली, जिसमें खेमचंद के नाम पर सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, पर्यवेक्षक तरुण चुच की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में विस्तार से हुई विधायक दल की बैठक में कई नामों पर विचार हुआ था। चर्चा थी कि कुकी ब्रनाम मैतेई समुदाय के बीच संतुलन साधने के लिए नई सरकार में कुकी समुदाय को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में लिए गए निर्णय से साफ था कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पसंद को तबज्जो नहीं मिली। बीरेन सात बार के विधायक मैतेई समुदाय के ही गोविंद दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



समन्वय वाली
राजस्थान सरकार

राजस्थान में आयोजित
भारत की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय

पत्थर उद्योग प्रदर्शनी

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

JAIPUR
ARCHITECTURE
FESTIVAL

6th-7th February 2026
JECC, SITAPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

5 फरवरी, 2026 | प्रातः 9:30 बजे
मुग्धा कन्वेंशन हॉल, जेईसीसी, सीतापुरा, जयपुर

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 में पहली बार

26+ अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में
इंडिया स्टोनमार्ट की वेबसाइट

स्टोनमार्ट का
स्मार्ट डिजिटल मोबाइल ऐप

अब तक का सबसे
विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र

विद्यार्थियों के लिए
प्रतियोगिताएँ

पत्थर उद्योग और आध्यात्मिक
संस्थानों के बीच सहयोग

'एक जिला - एक उत्पाद'
(ODOP) पवेलियन

एमएसएमई (MSME)
केन्द्रित प्रमोशन और स्टॉल इंटीग्रेशन

आप सादर आमंत्रित हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: www.stonemart-india.in info@stonemart-india.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्हाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908